navbharat
Mega Developers

DHARAVI COMPILED MEDIA REPORT
08 Apr, 2025 - 09 Apr, 2025

Total Mention 12

Print	Financial	Mainline	Regional	Periodical
3	N/A	1	2	N/A

Tv	Business	English	Hindi	Regional
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Online
9

Print

No	Newspaper	Headline	Edition	Pg
1.	Free Press Journal	Dharavi mapping nearly over; one lakh tenements numbered	Mumbai	5
2.	Navbharat	Large participation of residents in Dharavi survey	Mumbai	4
3.	Nav Rashtra	Dharavi residents' response to survey so far has been overwhelming	Mumbai	4

Free Press Journal • 09 Apr • Dharavi

Dharavi mapping nearly over; one lakh tenements numbered

5 • PG | 249 • Sqcm | 197890 • AVE | 251.68K • Cir | Bottom Left
Mumbai

Dharavi mapping nearly over; one lakh tenements numbered

Minor voluntary exclusions remain in Kumbharwada, 13th compound, and a few individuals aligned with specific political ideologies

FPJ News Service
MUMBAI

The mapping of Dharavi is nearing completion with close to one lakh tenements already numbered. This indicates overwhelming participation and a sense of anticipation among Dharavikars, who have long awaited development of the area. Those few who have not participated so far have either opted out voluntarily or have chosen not to engage in the survey because of political ideologies.

The survey numbers are becoming staggering day by day as it enters its final lap. As per latest figures, lane recce has been completed for approximately 99,000 tenements, and over 93,000 tenements have been numbered. Household survey has been completed for more than 67,847 tenements.

The Dharavi survey is being conducted in four stages. In the first stage, survey teams conduct a physical reconnaissance of every lane and by-lane to assess the structurers. In the second stage, each house is given a unique identification number. In the third stage, digital mapping of every structure is done through Lidar technology. In the fourth and final stage, survey teams visit and collect documents from tenement holders.

To ensure no one is left behind, the Dharavi Redevelopment Project (DRP)/SRA of Government of Maharashtra, recently extended the deadline to submit documents from March 31, 2025, to April 15, 2025. It was widely communicated through newspaper advertisements.

Even though CM Devendra Fadnavis and DRP CEO SVR Srinivas have categorically mentioned that the Dharavi project is aimed at housing for all, the government's plans are attacked by the opposition thereby confusing a section of gullible Dharavikars and their own devout followers. According to them, DRP is making efforts to declare thousands of residents ineligible, which will lead to conflict in Dharavi.

Commenting on the issue, an NMDPL spokesperson said, "Our endeavour is to provide homes and commercial galas to all eligible tenement holders within Dharavi Notified Area (DNA), and all qualified ineligible residential tenement holders outside Dharavi but within MMR. We do not intend to leave out anyone as per GoM's vision for a slum-free Mumbai. The project is being executed as per provisions of the project tender and, as developers, we shall comply with the policies are laid out by the government."

According to the NMDPL spokesperson, barring approximately 15,150 tenements belonging to Kumbharwada, 13th compound and a few owing to their allegiance to specific political ideology, all Dharavikars have been fully covered and would get proper homes, commercials shops and galas.

However, it has been learnt that these 15,150 odd tenements have been informed to come forward by April 15, 2025, beyond which they would be left behind and they wouldn't qualify for benefits under the redevelopment project. As per rules, in due course, all illegal settlements are removed.

Navbharat • 09 Apr • Dharavi

Large participation of residents in Dharavi survey

4 • PG | 285 • Sqcm | 213567 • AVE | 675K • Cir | Bottom Right | Mumbai Plus

Mumbai

धारावी के सर्वे में निवासियों की बड़ी भागीदारी

एक लाख मकानों को नम्बर आवंटित

केवल कुछ राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े व्यक्ति ही बचे हैं

मुंबई. धारावी के विकास का मानचित्रण लगभग पूरा होने वाला है तथा लगभग एक लाख मकानों को नम्बर आवंटित कर दिए गए हैं. यह धारावी के निवासियों की भागीदारी और उत्सुकता की जबरदस्त भावना को दर्शाता है, जो लंबे समय से इस क्षेत्र के विकास की प्रतीक्षा कर रहे थे. जिन कुछ लोगों ने अब तक इस अभ्यास में भाग नहीं लिया है, उन्होंने या तो स्वेच्छा से भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है या फिर राजनीतिक विचारधाराओं के कारण सर्वेक्षण में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है. जैसे-जैसे सर्वेक्षण अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है, इसके आंकड़े दिन-प्रतिदिन अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं. नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, लगभग 99,000 मकानों के लिए लेन सुधार का कार्य पूरा हो चुका है, तथा 93,000 से अधिक मकानों की संख्या निर्धारित कर ली गई है. 67,847 से अधिक मकानों के लिए घरेलू सर्वेक्षण पूरा हो चुका है. धारावी सर्वेक्षण चार चरणों में किया जा रहा है. प्रथम चरण में, सर्वेक्षण दल संरचनाओं का आकलन करने के लिए प्रत्येक गली और उप-गली का भौतिक ताला खोलते हैं. दूसरे चरण में, प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाती है. तीसरे चरण में, 'लिडार' तकनीक का उपयोग करके प्रत्येक संरचना का डिजिटल मानचित्रण किया जाता है. चौथे और अंतिम चरण में सर्वेक्षण दल मकान मालिकों से दस्तावेज एकत्रित करते हैं.

दस्तावेज जमा करने की समय सीमा 15 अप्रैल

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी वहां न रुके, महाराष्ट्र सरकार की धारावी पुनर्विकास परियोजना (डीआरपी)/एसआरए ने हाल ही में दस्तावेज जमा करने की समय सीमा 31 मार्च, 2025 से बढ़ाकर 15 अप्रैल, 2025 कर दी है. समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर इसका व्यापक प्रचार किया गया. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डीआरपी के सीईओ एस.वी.आर. श्रीनिवास स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि धारावी परियोजना का उद्देश्य सभी के लिए घर बनाना है, लेकिन विपक्ष सरकार की योजना में बाधाएं उत्पन्न कर रहा है, जिससे धारावी निवासियों और उनके

सभी पात्र निवासी होंगे कवर

इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए नवभारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (एनएमडीपीएल) के प्रवक्ता ने कहा, ₹हमारा प्रयास धारावी अधिसूचित क्षेत्र (डीएनए) में सभी पात्र निवासियों और गालाधारकों को घर और व्यावसायिक सुविधाएं प्रदान करना है. महाराष्ट्र सरकार के झुग्गी-झोपड़ी मुक्त मुंबई के दृष्टिकोण के अनुसार, हमारा इरादा किसी को भी वंचित नहीं करना है. परियोजना को परियोजना निविदा के प्रावधानों के अनुसार शुरू किया जा रहा है और डेवलपर्स के रूप में, हम सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों का पालन करेंगे.₹ प्रवक्ता के अनुसार, कुंभारवाड़ा और 13वें कम्पाउंड में लगभग 15,150 मकानों को छोड़कर और एक विशेष राजनीतिक विचारधारा के प्रति उनकी निष्ठा के कारण, सभी धारावीकरों को पूरी तरह से कवर किया गया है और उन्हें उपयुक्त घर और व्यावसायिक दुकानें मिलेंगी. हालांकि, यह पता चला है कि इन अनुमानित 15,150 से अधिक मकानों को 15 अप्रैल, 2025 तक आगे आने के लिए अधिसूचित किया गया है, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा और वे पुनर्विकास परियोजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे. नियमों के अनुसार, समय के साथ सभी अवैध बस्तियां हटा दी जाती हैं.

अनुयायियों के एक वर्ग में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है. उनके अनुसार, डीआरपी हजारों निवासियों को अयोग्य घोषित करने का प्रयास कर रही है, जिससे धारावी में संघर्ष पैदा होगा.

Nav Rashtra • 09 Apr • Dharavi

Dharavi residents' response to survey so far has been overwhelming

4 • PG | 281 • Sqcm | 464418 • AVE | 500.5K • Cir | Bottom Right | Mumbai Plus

Mumbai

धारावीत आजवरच्या सर्वेक्षणाला स्थानिकांचा उदंड प्रतिसाद

कुंभारवाडा, १३ व्या कंपाऊंडसह काही अपवाद वगळता स्थानिकांचे संपूर्ण सहकार्य

१ लाख बांधकामांवर टाकण्यात आले क्रमांक

मुंबई. काही मोजके अपवाद वगळता धारावीत आजवरच्या शासकीय सर्वेक्षणाला धारावीकरांचा उदंड प्रतिसाद लाभला आहे. आजवरच्या सर्वेक्षणात सुमारे १ लाख बांधकामांवर (सदनिका/गाळे) क्रमांक टाकण्यात आला असून यामुळे सर्वेक्षणातील सकारात्मक लोकसहभाग अधोरेखित झाला आहे. ज्या मोजक्या स्थानिकांनी स्वेच्छेने अथवा राजकीय विचारधारेने प्रेरित होऊन या सर्वेक्षणात अद्याप सहभाग नोंदवला नाही, त्यांना येत्या 15 एप्रिल पर्यंत सर्वेक्षणात सहभागी होण्याचे आवाहन धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या वतीने करण्यात आले आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची पहिली पायरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शासकीय सर्वेक्षणात दिवसागणिक नवे उच्चांक प्रस्थापित केले जात आहेत. ताज्या आकडेवारीनुसार, आजवर ९९ हजारांहून अधिक बांधकामाची लेन रेकी करण्यात आली असून सुमारे ९३ हजार सदनिकांवर क्रमांक टाकण्यात आला आहे.

आजवर सुमारे ६७ हजार ८४७ बांधकामाचे प्रत्यक्ष (डोअर टू डोअर) सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. धारावीत सर्वेक्षणाची प्रक्रिया ४ टप्प्यांमध्ये राबवली जात आहे. पहिल्या टप्प्यात सर्वेक्षण करणाऱ्या पथकाच्या वतीने गल्लीबोळांची लेन रेकी करण्यात येते. दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्येक घराला युनिक आयडी क्रमांक देण्यात येतो. लीडार तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने डिजिटल मॅपिंगचा तिसरा टप्पा पूर्ण झाल्यावर चौथ्या टप्प्यात सर्वेक्षण पथकाकडून प्रत्यक्ष घरोघरी जाऊन सदनिकाधारकांच्या कागदपत्रांची पडताळणी केली जाते.

सर्वेक्षणात सहभागी होण्याची मुदत १५ एप्रिल : पुनर्विकासापासून कोणीही वंचित राहू नये म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्प / झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए/ डीआरपी) च्या वतीने सर्वेक्षणात सहभागी होण्याची मुदत ३१ मार्च २०२५ पासून १५ एप्रिल २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

वृत्तपत्रातील जाहिरातींच्या माध्यमातून धारावीकरांना याबाबतची माहिती देण्यात आली. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात एकाही स्थानिकाला डावलले जाणार याची ग्वाही प्रत्यक्षात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांनी याआधीच दिली आहे. मात्र, विरोधक या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाबाबत अपप्रचार करून स्थानिकांमध्ये संभ्रम निर्माण करत आहेत.

सर्व पात्र रहिवाशांना कव्हर केले जाईल

धारावीतील सर्व पात्र रहिवाशांना आणि गाळेधारकांना धारावी नोटिफाईड एरिया (डीएनए) मध्येच नवी सदनिका अथवा व्यापारी गाळा देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. तसेच सर्व अपात्र धारावीकरांना धारावीबाहेर मुंबई महानगरप्रदेशात सदनिका देण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र शासनाचे झोपडपट्टीमुक्त मुंबईचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी या पुनर्विकासात कोणीही बाहेर फेकले जाणार नाही, याची दक्षता आम्ही घेत आहोत. हा पुनर्विकास प्रकल्प निविदेतील नियमावलीनुसार राबविला जात असून शासनाच्या धोरणानुसार याची अंमलबजावणी करण्याची विकासक म्हणून आमची जबाबदारी आहे, अशी प्रतिक्रिया नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड (एनएमडीपीएल) च्या प्रवक्त्याने दिली. तसेच केवळ सुमारे १५ हजार १५० सदनिकांचा अपवाद वगळता आजवरच्या सर्वेक्षणात धारावीकरांनी संपूर्ण सहभाग नोंदवला आहे. कुंभारवाडा, १३ वे कंपाऊंड आणि राजकीय विचारधारेने प्रेरित काही स्थानिकांनी या सर्वेक्षणात सहभाग घेतला नाही, अशी पुस्तीही प्रवक्त्याने जोडली. आजवरच्या सर्वेक्षणात सहभागी न झालेल्या या १५ हजार १५० सदनिकाधारकांनी येत्या १५ एप्रिल पर्यंत सर्वेक्षणात सहभाग घेण्याचे आवाहन करण्यात आले असून या मुदतीत सर्वेक्षण न झालेल्या सदनिकाधारकांना पुनर्विकासात सामावून घेतले जाणार नाही. तसेच, नियमानुसार त्यांच्या सदनिका अनधिकृत ठरवून त्यांना निष्कासित करण्यात येईल.

Mumbai's Dharavi redevelopment survey received strong participation, with over 90,000 homes surveyed, despite opposition from a few locals. The survey, part of a multi-phase process, aims to include all eligible residents. Influenced by political ideologies, non-participants were urged to join by April 15 to avoid exclusion from redevelopment.

Online Coverage

No	Portal Name	Headline (Incorporated with URL)	Reach
1.	Hindustan Times	State to revive its iconic Aarey milk brand	124.6M
2.	Oneindia News	Mumbai"s Iconic ‘Aarey" Milk Brand Makes A Comeback — Minus Its Dairy Colony R...	35.9M
3.	Dailyhunt	Mumbai"s Iconic "Aarey" Milk Brand Makes A Comeback - Minus Its Dairy Colony ...	18.6M
4.	Free Press Journal	Near-Total Participation In Dharavi	6.4M
5.	Free Press Journal	Mumbai"s Iconic Aarey Milk Brand Set To Make A Comeback; Here"s How	6.4M
6.	Hotlinenews	ધારાવીના સર્વેમાં લગભગ તમામની સહભાગીતા જોવા મળી	N/A
7.	OB News	Mumbai"s Iconic Aarey Milk Brand Set To Make A Comeback; Here"s How	N/A
8.	The Mobi World	Mumbai"s Iconic Aarey Milk Brand Set To Make A Comeback; Here"s How	N/A
9.	Newspoint	Mumbai"s Iconic Aarey Milk Brand Set To Make A Comeback; Here"s How	N/A